भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 743
बुधवार, दिनांक 04 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संबंधी रिपोर्ट</u>

743. श्री तनुज पुनियाः
श्री कार्ती पी. चिदम्बरमः नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दिसंबर 2025 की संसदीय समिति की रिपोर्ट पर ध्यान दिया है जिसमें बताया गया था कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 243 गीगावाट है और देश में वर्तमान में ऊर्जा भंडारण की क्षमता केवल लगभग 5.5 गीगावाट है जबकि वर्ष 2030 तक अनुमानित आवश्यकता 61 गीगावाट की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भंडारण प्रौद्योगिकियों के घरेलू अनुसंधान और विनिर्माण के लिए सहायता सहित इस अंतर को पाटने के लिए उठाए जा रहे विशिष्ट कदम क्या हैं;

(ग) जून 2025 तक लगभग 44 गीगावाट सौर क्षमता के लिए निविदाएं आमंत्रित किए जाने के बावजूद विद्युत खरीद समझौते अहस्ताक्षरित रहने के कारण क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है कि डिस्कॉम अपने नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्वों को पूरा करें और भविष्य की निविदाएं राज्यों की वास्तविक मांग के अनुरूप हों; और

(ङ) क्या सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा पारेपण परियोजनाओं में विलंब को दूर करने और केंद्रीय एवं राज्य प्राधिकरणों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित उपाय लागू किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) एवं (ख): केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने "इष्टतम उत्पादन मिश्रण 2030" पर अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि वर्ष 2029-30 तक आवश्यक ऊर्जा भंडारण क्षमता 60.63 गीगावॉट होगी, जिसमें पंप्ड भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) से 18.98 गीगावॉट और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) से 41.65 गीगावॉट शामिल हैं।

सरकार ने देश में ऊर्जा भंडारण क्षमता के विकास के लिए निम्नलिखित प्रमुख उपाए किए हैं जिनमें स्वदेशी अनुसंधान और भंडारण प्रौद्योगिकियों के विनिर्माण के लिए सहायता शामिल है:

- सहायक सेवाओं के साथ-साथ उत्पादन, पारेषण और वितरण परिसंपत्तियों के हिस्से के रूप में बीईएसएस की खरीद और उपयोग के लिए दिशानिर्देश। अधिसूचित
- देश में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क जारी किया गया।
- पीएसपी को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।